

भारत की प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा देना

यह एडिटरियल 01/06/2022 को 'लाइवमटि' में प्रकाशित "Is It Time for India to go for Competitiveness Legislation" लेख पर आधारित है। इसमें भारत की प्रतस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि लाने के मार्ग की चुनौतियों और इस संबंध में भारत द्वारा किये जा सकने वाले उपायों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

भारत अपनी अर्थव्यवस्था में बेहतर प्रतस्पर्द्धात्मकता पाने के लिये सुधार के पथ पर नरितर है। डिजिटल विकास, व्यापार नीति सुधार और आंतरिक व बाह्य-मुखी उपायों के एक मशिरण सहति ये आर्थिक सुधार गरीबी को कम करने एवं बेहतर रोजगार सृजति करने के एजेंडे के साथ और भारत की प्रतस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि करने के लिये लागू किये गए हैं।

- हालाँकि भारत की प्रतस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने में अभी भी कई बाधाएँ मौजूद हैं, जैसे कि अवकिसति वनिरिमाण क्षेत्र, कोवडि-19 का प्रभाव और तकनीकी एवं ढाँचागत चुनौतियाँ।

भारत की प्रतस्पर्द्धात्मकता की विकास गाथा

- वर्ल्ड कॉम्पिटिविनेस ईयरबुक (World Competitiveness Yearbook- WCY) के अनुसार भारत ने [वार्षिक विश्व प्रतस्पर्द्धात्मकता सूचकांक](#) (World Competitiveness Index) में 43वाँ स्थान बनाए रखा है।
 - [ब्रकिस](#) देशों में भारत, चीन (16वें) के बाद दूसरे (43वें) स्थान पर है, इसके बाद रूस (45वें), ब्राज़ील (57वें) और दक्षिण अफ्रीका (62वें) का स्थान है।
 - भारत की शक्ति दूरसंचार (प्रथम), मोबाइल टेलीफोन लागत (प्रथम), आईसीटी सेवाओं के नरियात (तीसरे), सेवा व्यवसायों में पारशिरमकि (चौथा) और व्यापार सूचकांक (पाँचवें) में नविश में नहिंति है।
- [वैशविक नवाचार सूचकांक](#) (Global Innovation Index- GII) 2021 रैंकिंग में भारत की स्थिति में दो स्थानों का सुधार हुआ है तथा भारत 46वें स्थान पर आ गया है।
 - GII में भारत पछिले कुछ वर्षों से ऊपर की ओर बढ़ रहा है।
 - भारत ने वर्ष 2021 में 'इनोवेशन इनपुट' की तुलना में 'इनोवेशन आउटपुट' में बेहतर प्रदर्शन कया।
 - मध्य और दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले स्थान पर है।
- भारत ने वनिरिमाण क्षमता में प्रतयास्यता (Resilience) सुनश्चिति करने के लिये सराहनीय प्रयास कये हैं, जहाँ ['आत्मनरिभर भारत'](#) और ['मेक इन इंडिया'](#) जैसे उसके पहले घरेलू आपूर्त शृंखलाओं और वनिरिमाण केंद्रों में भारी नविश पर लकषति हैं।
 - सरकार ने भारत की वनिरिमाण क्षमताओं और नरियात को बढ़ावा देने के लिये वभिन्नि क्षेत्रों में उत्पादन-लकिड प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरु की है।
- प्रतस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकीय प्रगतिको सुवधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारत के दूरसंचार वभिग (DoT) ने 6G प्रौद्योगिकी पर छह कार्यबलों/टास्क फोरस का गठन कया है।
 - वदिश मंत्रालय, अपने 'नेस्ट' प्रभाग के माध्यम से प्रौद्योगिकी व्यवस्था से संबंधति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रयि भागीदारी सुनश्चिति कर रहा है।

'नई और उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियाँ'

- वर्ष 2020 में वदिश मंत्रालय ने एक नए प्रभाग ['नई और उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियाँ'](#) (New and Emerging Strategic Technologies- NEST) की स्थापना की।
- यह नई और उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधति वषियों के लिये मंत्रालय के भीतर नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वदिशी भागीदारों के साथ साझेदारी में सहायता प्रदान करता है।
- इसे घरेलू हतिधारकों के साथ समन्वय में और भारत की विकास संबंधी प्राथमकिताओं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों के अनुरूप भारत की बाह्य प्रौद्योगिकी नीति विकिसति करने का भी दायतिव सौपा गया है।

- यह नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों और प्रौद्योगिकी-आधारित संसाधनों के वंश नीति एवं अंतरराष्ट्रीय वधिक नहितार्यों के आकलन में भी मदद करेगा तथा उपयुक्त वंश नीति विकल्पों की अनुशंसा करेगा।
- NEST बहुपक्षीय एवं वविधि-पक्षीय ढाँचे में भारत की परस्थितियों के अनुकूल प्रौद्योगिकी व्यवस्था नयियों, मानकों और संरचना पर वारता भी करता है।

भारत की प्रतसिपर्द्धात्मकता बढ़ाने के राह की चुनौतियाँ

- **नरियात प्रतसिपर्द्धात्मकता की चुनौतियाँ:** कमज़ोर व्यापार समर्थन, नरियात अवसंरचना में अंतराल, बुनियादी व्यापार समर्थन, वृत्तीय सुवधियों तक पहुँच की कमी, कम नरियात ऋण आदि वे दोष हैं जो कई राज्यों में नरियात तत्परता (Export Preparedness) में बाधा पहुँचाते हैं।
- **अपर्याप्त अनुसंधान एवं वकिस:** देश भर में अनुसंधान एवं वकिस (R&D) अवसंरचना में व्यापक सुधार की गुंजाइश है। भारत में अनुसंधान एवं वकिस अवसंरचना के मामले में उच्च क्षेत्रीय असमानता की भी स्थिति है।
 - वैश्वीकरण की उभरती हुई प्रकृति (जो उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और नवाचार को पहले से कहीं अधिक महत्त्व देगा) के संदर्भ में भारत की लागत प्रतसिपर्द्धात्मकता वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसे स्थापित कर सकने हेतु पर्याप्त प्रकट नहीं होती है।
 - R&D में धीरे-धीरे सुधार दीर्घकाल में बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा।
- **अपर्याप्त अवसंरचना:** अवसंरचना भारत की सबसे कमज़ोर कड़ी बनी हुई है। बजिली, संचार, जल और अपशिष्ट जैसे वभिन्न क्षेत्रों तक अवसंरचना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में परविहन अवसंरचना सर्वाधिक महत्त्व रखती है।
 - भारत की अवकिसति परविहन अवसंरचना नरियातकों के लिये कई समस्याएँ उत्पन्न करती है, जिनमें से प्रमुख हैं:
 - भीड़भाड़ भरे बंदरगाह
 - भीड़भाड़ भरी सड़कें
 - कनेक्टिविटी की कमी
 - पुराने रेल उपकरण
- **अल्प-वकिसति वनरिमाण क्षेत्र:** जबकि पड़ोसी के साथ ही प्रतसिपर्द्धी देश चीन देश को श्रम-प्रधान वनरिमाण से आगे और रोबोटिकस एवं एरोस्पेस जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में ले जाने के लिये वर्तमान में एक 10-वर्षीय परविरतनकारी अभियान 'मेड इन चाइना 2025' के मध्य में है, भारत इसके वपिरित अभी भी पुराने दृष्टिकोण पर आधारित श्रम-गहन वनरिमाण को अपनी ऐसी अर्थव्यवस्था में लाने का लक्ष्य बना रहा है जसि लाखों नए रोजगार सृजित करने की गंभीर आवश्यकता है।
 - पछिले दो वर्षों में इस तुच्छ लक्ष्य को भी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से आघात लगा है।
- **कम तकनीकी समझ:** सीमिति समझ और अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण छोटे, स्थानीय व्यवसाय प्रायः डिजिटल समाधान अपनाने में संकोच रखते हैं।
 - चौथी औद्योगिक क्रांति की नई प्रौद्योगिकियों (AI, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिकस एवं अन्य संबंधित प्रौद्योगिकियों) का उदय संगठित वृहत वनरिमाण की तुलना में MSMEs के लिये अधिक बड़ी चुनौती है।

अपनी प्रतसिपर्द्धात्मकता में सुधार के लिये भारत को क्या करना चाहिये?

- **नीतितगत हस्तक्षेप:** भारत की प्रतसिपर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये आवश्यक स्तंभों में से एक होगा 'समग्र सरकार' का दृष्टिकोण ('Whole of Government' Approach) जो केंद्र के भीतर और राज्यों के साथ और उनके बीच घटित होगा।
 - यह भारत के लिये एक ऐसे कानून और संस्थान पर वचार करने का समय है जो सभी संगठनों को प्रतसिपर्द्धात्मकता को आगे बढ़ाने के लिये राजी कर सके।
 - व्यापार प्रतसिपर्द्धा, क्षमता नरिमाण और आपूर्ति शृंखला प्रत्यास्थता प्राप्त करने के लिये एक सुदृढ़ संस्थागत संरचना आवश्यक है।
 - मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर वारता के लिये भी यह एक पूर्व-शर्त है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के वकिस के लिये महत्त्वपूर्ण है।
 - एक नए कानून के तहत एक 'राष्ट्रीय प्रतसिपर्द्धा आयोग' (National Competitiveness Commission) का गठन भारतीय वनरिमाण उद्योगों के वकिस को सक्रिय करने और बनाए रखने हेतु नीतितगत संवाद के लिये एक मज़बूत मंच प्रदान कर सकता है।
- **अमूर्त आस्तियों में नविश:** भारत को 'भवषिय के अनुकूल' कौशल नरिमाण के साथ-साथ स्वास्थ्य और शकिसा जैसी अमूर्त आस्तियों में बेहतर और उच्च नविश की आवश्यकता है।
 - जहाँ तक नीतियों और ववित्तपोषण का संबंध है, इन मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ साझेदारी में राज्यों द्वारा कार्य किया जाना चाहिये।
 - हालॉक 'वन साइज़ फटिस ऑल' का दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं होगा, इसलिये राज्यों को अपनी स्वयं की रणनीति वकिसति करने का अवसर दिया जाना चाहिये।
 - 'पीपल फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप' (People-first Public-Private Partnerships) को बढ़ावा देने की क्षमता का उपयोग ववित्त जुटाने के लिये किया जाना चाहिये ताकि स्वास्थ्य, नौकरियों एवं कौशल को कवर किया जा सके और सभी हतिधारकों के परामर्श से प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **FTAs पर फोकस:** FTAs उद्योगों को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भाग लेने में मदद करते हैं। अंतरा- और अंतर-क्षेत्रीय फर्म-स्तरीय सहयोग एवं भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
 - FTAs को PLI योजनाओं को भी प्रकता प्रदान करना चाहिये ताकि जनि उत्पादों के नरिमाण को घरेलू स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाता है, वे वैश्विक स्तर पर प्रतसिपर्द्धा कर सकें।
- **अनुसंधान एवं वकिस पर ध्यान देना:** उत्तर-कोवडि वशिव में भारत को वैश्विक बाज़ार में अपनी स्वयं की जगह बनाने की ज़रूरत है। इस प्रकार, नीति और अवसंरचना संबंधी कर्मियों को दूर कर भारतीय राज्यों की क्षमताओं का दोहन करना आवश्यक है।
 - इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि अधिक वकिसति राज्य भारत के लिये उस जगह के नरिमाण के दृष्टिकोण से अनुसंधान एवं वकिस

अवसंरचना में सुधार की दशा में ध्यान केंद्रित करें।

- ऐसा इसलिये आवश्यक है क्योंकि अनुसंधान एवं विकास अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वृहत नवाचार को सक्रिय करते हैं।

भारत को किस ओर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है?

- इस परिप्रेक्ष्य में अर्द्धचालकों या सेमीकंडक्टर्स ने मुख्य भूमिका प्राप्त कर ली है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भू-अर्थशास्त्र और भू-राजनीति को आकार देने में सेमीकंडक्टर्स (और डिजिटलीकरण) ने तेल को प्रतिस्थापित कर दिया है।
 - कोविड-प्रति आपूर्ति शृंखला व्यवधान, चीन द्वारा नरियात नियंत्रण और रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत के लिये एक सेमीकंडक्टर्स वनिरिमाण आधार का निर्माण करना अनिवार्य हो गया है।
- अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) शामिल है।
 - अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिये भारत को 6G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना चाहिये। इससे FTA वार्ताओं में भी हमारी स्थिति सुदृढ़ करने में भी मदद मिलेगी।
- कर बोझ को कम करना, विशेष रूप से MSME क्षेत्र के लिये, भी आवश्यक है ताकि उनकी लाभप्रदता में वृद्धि हो। श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिये सरकार की ओर से और अधिक समर्थन की ज़रूरत है।
- इसके साथ ही गैर-टैरिफि कारकों पर भी कार्रवाई की आवश्यकता है; नवाचार को प्रोत्साहित करना, बौद्धिक संपदा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, रसद लागत को कम करना और व्यवसाय संचालन को सुगम बनाना भी महत्त्वपूर्ण है।

अभ्यास प्रश्न: “वभिन्न आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बावजूद भारत की प्रतिस्पर्धात्मक भावना प्रायः अल्प-विकसित वनिरिमाण क्षेत्र, अनुसंधान एवं विकास की कमी, ढाँचागत चुनौतियों और सीमिति प्रौद्योगिकीय ज्ञान जैसे मुद्दों के नीचे दबी रह जाती है।” टिप्पणी कीजिये।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/enhancing-competitiveness-of-india>

